

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

28-06-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या-544/2006, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक श्री अरविन्द कुमार, पिता-स्व० नवल किशोर शर्मा, सा०-घोसवरी, थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-05-04/2006 में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दिनांक-10.01.2012 को माननीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुए उसे पुनर्विचार हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में वाद की कार्रवाई पुनः आरम्भ करते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-28.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे कृषक हैं। उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक-676/गो०, दिनांक-02.05.2013 द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में मात्र अग्रसारित किया गया है, अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अनुशंसित एवं अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध थाना अभिलेख में किसी प्रकार का शिकायत दर्ज नहीं है। इनका नाम एवं पता सही पाया गया है। आवेदक द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 की कंडिका-II में एन०पी०बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :-

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका-II की उप कंडिका-b तथा e निम्नवत है :-

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

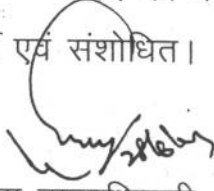
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/ 16/2009, शस्त्र

दिनांक-31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री अरविन्द कुमार, पिता-स्व0 नवल किशोर शर्मा, सा0-घोसवरी, थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।